वैज्ञानिकों ने बोर्नियो के अंधेरे जंगलों में एक अजीब से मांसाहारी पौधे की खोज की है, जो अपने शिकार को जमीन के अंदर पकड़ता है। चैक वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय टीम ने पुष्टि की है कि, ''निपेंथस पुडिका'' पिचर प्लांट की ऐसी पहली प्रजाति है, जिनके पौधे जमीन के अंदर शिकार करते हैं। पिचर प्लांट मुख्यतः दक्षिणपूर्व एशिया में मिलते हैं। ऊपर चढ़ने वाली इन लताओं की पत्तियाँ रंगीन और जग के आकार की होती हैं जिनमें तरल पदार्थ होता है। पत्ती के सिरे पर बैठने वाले कीड़ों को ये पत्तियां अंदर खींच लेती हैं। यूरोप में ये पौधे काफी लोकप्रिय हैं, जहां 18 वीं सदी से इन्हें लोग अपने बगीचों में उगाते हैं। पैलकी युनिवर्सिटी के डिपार्टमैंट ऑफ इकॉलजी एण्ड एनवायरमैंट के मार्टिन डैनका ने कहा ''हमने एक ऐसा पिचर प्लांट खोजा है, जो अन्य ज्ञात प्रजातियों से एकदम अलग व्यवहार करता है। इस नई प्रजाति के फूलों के कप जमीन में 11 सैंटीमीटर अंदर होते हैं तथा जमीन के अंदर मिलने वाले अकशेरुकी जीवों, खासकर चींटियों, विभिन्न प्रकार की दीमक व बीटल्स को खा जाते हैं। फूलों के कप्स में मीठा तरल भरा होता है जो कीटों को आकर्षित करता है और एक बार कोई जीव जब पिचर में गिर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता, वहीं मर जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मांसाहारी प्रजाति अपने ट्रैप्स को भूमि के नीचे इसलिए छुपाती है क्योंकि, संकड़ी पहाड़ियाँ, जिन पर ये पौधे उगते हैं, तुलनात्मक रुप से जल्दी सूख जाती हैं। दूसरी तरफ भूमिगत कन्दराओं में नमी होती है और भोजन की भरमार भी। वैज्ञानिकों को सबसे पहले ये पिचर एक पेड़ के नीचे गुहिका में छुपे मिले थे। विशेषज्ञ लुबोस महिस्की ने बताया, ''इसके बाद हमने ऐसे ही कई पेड़ देखे, हमने पाया कि इस प्रजाति की शाखाएं जमीन में जाती हैं।'' वैज्ञानिकों का मत है कि मांसाहारी पौधों की इस प्रजाति की खोज से स्थानीय वनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। टीम में शामिल इण्डोनेशिया के वैज्ञानिक वेविन जिआस्मान्तो ने कहा कि, यह खोज इण्डोनेशिया में नेचर कंज़र्वेशन के लिए महत्वपूर्ण है, इससे बोर्निओ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इसकी जैव विविधता की महत्ता स्पष्ट होती है। वेविन इण्डोनेशियन सैंटर फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ वैंटलैंड बायोटॉप्स के लिए काम करते हैं।

'आप कभी मुझे जवाब क्यों नहीं देते?'

अहमद पटेल के पुत्र, फैज़ल पटेल ने मु.मंत्री के ओ.एस.डी. शशिकांत शर्मा पर आरोप लगाया कि, ओ.एस.डी. उनके फोन तक नहीं उठाते

- **फैज़ल पटेल ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि, अल्पसंख्यक पृष्ठ भूमि के गरीब लोग मुझसे सम्पर्क करते हैं तथा साधारण कामों के लिये मदद मांगते हैं। मेरे दिवंगत पिता के बाद वे मुझसे उनकी समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद करते हैं।**
- **बसपा मूल के विधायक वाजिब अली व वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अमीन खां भी अल्पसंख्यकों के काम न होने पर नाराजगी जता चुके हैं।**

जयपुर, 20 अगस्त (का.प्र.)। राजनीति में समय कितना तेजी के साथ बदलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अहमद पटेल का परिवार। जब अहमद पटेल जिंदा थे, तो उनकी कही गई बातों की कांग्रेस में अक्षरश: पालना होती थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि उनके पुत्र को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर लिखकर कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी फोन तक नहीं उठाते। दरअसल अहमद पटेल के पुत्र फैसल ने एक ट्वीट करके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी शशिकांत शर्मा पर सीधे आरोप लगाते हुए लिखा है कि '' शशिकांत शर्मा, तुम कभी मुझे जवाब क्यों नहीं देते?

इस ट्वीट के बाद खलबली मचना तय थी, और हुआ भी ऐसा ही। बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया और इसके बाद फैसल ने यह ट्वीट हटा भी दिया, लेकिन यह ट्वीट तब तक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था।

गांधी परिवार के सबसे नजदीकी और कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार रहे दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल कांग्रेस में अपनी अनदेखी को लेकर नाराजगी जताते आए हैं।

फैसल पटेल का एक ट्वीट अलसुबह 4 बजकर 57 मिनट पर पोस्ट हुआ, जिसमे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी को निशाने पर लिया गया था। इस ट्वीट के सामने आते ही कांग्रेस नेताओं में चर्चा होनी ही थी। ऐसे में चर्चाएं हुई, तो डैमेज कंट्रोल का प्रयास करते हुए पांच घंटे बाद ट्वीट को डिलीट करा दिया गया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग करते हुए फैसल पटेल ने लिखा था – शशिकांत शर्मा, तुम कभी मुझे जवाब क्यों नहीं देते ? फैसल का कहना है कि अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के गरीब लोग मुझसे संपर्क करते हैं।

मुझसे राजस्थान में साधारण काम के लिए मदद मांगते हैं। मेरे दिवंगत पिता अहमद पटेल के बाद वे मुझसे उनकी समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद करते हैं।

अहमद पटेल ना सिर्फ कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ताकत देने के साथ मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है। फैसल पटेल को सार्वजनिक रूप से शशिकांत के खिलाफ लिखने की जरूरत पड़ी है, तो इसके राजनीतिक रूप से काफी गहरे मायने लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ बोलने के अलावा फैसल पटेल ने गरीब अल्पसंख्यकों के साधारण काम तक नहीं होने का भी मुद्दा उठाया है।

उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों के काम नहीं होने पर बसपा मूल के विधायक वाजिब अली भी नाराजगी जता चुके हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ मुस्लिम विधायक अमीन खान भी अल्पसंख्यक मंत्रियों को मजबूत विभाग नहीं देने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।

दरअसल फैसल पटेल ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए इसी साल अप्रैल में कहा था कि इंतजार करते-करते थक गया हूं। दरअसल फैसल पटेल का यह ट्वीट ऐसे समय पर आया है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद विधानसभा चुनावों के लिए कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। वहीं राजस्थान से गए मंत्री-विधायक भी विधानसभावार बैठक ले रहे हैं। इसलिए फैसल पटेल के इस समय किए गए इस ट्वीट के कई तरह के सियासी मायने हो सकते हैं।

बांग्लादेश की प्र.मंत्री शेख हसीना सितंबर में भारत आयेंगीं

- **दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस संबंध में आपस में चर्चा कर शेख हसीना और प्र.मंत्री मोदी के बीच मीटिंग के मुद्दे फिक्स कर रहे हैं।**

नई दिल्ली, 20 अगस्त। भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में व्यापार, संपर्क और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़ी चर्चा के आसार हैं। खबर है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत का दौरा करने जा रही हैं। वहीं, सितंबर में भारत आ सकती हैं। गुरुवार को ही हसीना ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के अधिकारों की बात की थी। उन्होंने अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों से अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानने की अपील की थी।

बांग्लादेश की पीएम हसीना 5 सितंबर को भारत आ सकती हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश मंत्रालय, सुरक्षा अधिकारियों और ढाका की टीम समेत भारत से इस दौरे के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि वह 8 सितंबर तक भारत में रहेंगी।

चार दिवसीय यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा वह जयपुर और अजमेर शरीफ की यात्रा कर सकती हैं। 8 सितंबर को उनके ढाका लौटने की संभावना है। खबर है कि पी.एम. मोदी अपनी बांग्लादेशी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअली स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन कर सकते हैं। 6 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, संपर्क और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है।

इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि भारत और बांग्लादेश सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग पर भी बातचीत कर सकते हैं।

खास बात है कि करोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार हसीना भारत यात्रा कर रही हैं। इससे पहले वह 2019 में भारत आई थीं। वहीं, पी.एम. मोदी बीती मार्च में बांग्लादेश गए थे।

आज राजीव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विस्तृत टैलीकॉम नैटवर्क के बिना भारत के आई.टी. और आई.टी.सर्विसेस वैश्विक ताकत नहीं बन सकती थीं जो बाद में बन गईं। 1980 में दशक में एक शहर से दूसरे शहर में किए जाने वाले फोन कॉल्स के खर्चों और जद्दोजहद को कोई याद कर सकता हैं। वे दु:स्वपन हुआ करते थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण अग्रिम सोच थी सिविल एविएशन सैक्टर को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना राजीव गांधी स्वयं एक दक्ष पायलट थे और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की एण्डियन एयरलाइन्स के विमान उड़ाए थे। उन्होंने वो समय देखा था जब सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों एयरलाइन्स की विभिन्न ट्रेड यूनियन्स पूरी इण्डस्ट्री के कामकाज को ठप्प कर दिया करती थीं।

यदि एक दिन ग्राउण्ड इंजीनियर्स हड़ताल करते तो अगले दिन पायलट्स गिल्ड कुछ भत्तों या सुविधाओं की मांगों को लेकर उड़ाने निलम्बित कर देती थीं। यह सरल किन्तु हताशापूर्ण था। कलकता से दिल्ली था किसी अन्य दो शहरों के कनफर्म एयर टिकट प्राप्त करने के लिए एयरलाइन्स हाउस को फोन करके अपने काम का अनुरोध करना पड़ता था।

एयर टैक्सी सर्विसेस से ही शुरूआत करें तो राजीव गांधी के शुरूआती प्रयोगात्मक कदमों ने ही समूचे एयरलाइन सैक्टर को आर्थिक रूप से उदार बना दिया। आज मैं आश्चर्य करता हूं कि भारत में कितने लोग देश के शहरों में फ्लाइट से आते जाते हैं, लेकिन इण्डियन एयरलाइन्स इण्डस्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत दबदबे से बाहर निकालने की शुरूआती सोच के बिना यह कैसे संभव हो सकता था।

क्रमश:

अशोक गहलोत नहीं चाहते राजस्थान की जनता को पानी मिले: शेखावत

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य के मु.मंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला

- **शेखावत ने कहा, केन्द्र ने 29 हजार करोड़ दिए, 4 हजार करोड़ भी खर्च नहीं किए, 25 हजार करोड़ पर सांप बन कर बैठे हैं।**
- **उन्होंने यह भी कहा कि, घर-घर पानी पहुंचाने की केन्द्र सरकार की योजना में देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान 30वें पायदान पर है।**

किशनगढ़ बास, 20 अगस्त (निसं)। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर-घर पानी पहुंचाने की योजना के तहत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को एक करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 29 हजार करोड़ रूपए दिए लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसमें से 4 हजार करोड़ रुपए भी जल योजना पर अभी तक खर्च नहीं किए हैं। 25 हजार करोड़ पर गहलोत सरकार सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात किशनगढ़ बास में पूर्व विधायक रामहेत यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से किए स्वागत के दौरान अपने संबोधन में कही।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को डर है की मोदी की योजना का पानी राजस्थान की जनता को पिला दिया तो वह कही हमको होने वाले चुनाव में पानी नहीं पिला दे। इस सोच के कारण आज हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले 30 व नंबर पर है।

हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ते देशभर में 10 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है।

उन्होंने कहा, एक कहावत है मोरिया पगा को देख कर खुद रोए हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, राजस्थान की सरकार राष्ट्रीय परियोजना की बात करती है मैं नदी परियोजना लेकर आऊंगा और योजना का 90 प्रतिशत पैसा देकर 2024 में होने वाले देश के चुनाव से पहले राजस्थान में घर-घर पानी पहुंचाने के संकल्प को पूरा कर नरेंद्र मोदी के सपनों को हम साकार करेंगे।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन के चलते महिलाएं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, साधु-संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है माफियाओं के हवाले प्रदेश को छोड़ा है। जनता एक-एक दिन का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा यह हमारे कार्यकर्ताओं की चूक का परिणाम है जो आज राजस्थान की आठ करोड़ जनता कांग्रेस सरकार के कुशासन की सजा भुगत रही है। 2023 के राजस्थान में होने वाले चुनाव से पहले पूरी ताकत के साथ भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और सरकार को बेनकाब कर नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाकर लाभ दिलाने का काम करेगा।

केंद्रीय मंत्री के पहुंचने से पहले पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक राम हेत सिंह यादव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में बिगड़ी अलवर जिले की कानून व्यवस्था व चरम सीमा पर पनप रहे भ्रष्टाचार और विकास में पिछड़ रहे अलवर जिले को लेकर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे किशनगढ़ बास पहुंचे थे।

शेखावत का राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना, अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, तिजारा पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव, जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका, यूआईटी चेयरमैन रहे देवी सिंह शेखावत सहित अनेक नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया।

डॉक्टरों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फार्मा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड के वाइस प्रैसिडैंट जयराज गोविन्द राजू ने कहा कि ''हमने कोविड महामारी के दौरान डोलो-650 पर निश्चित रूप से एक हजार करोड़ रूपए खर्च नहीं किए थे क्योंकि कोई भी कंपनी एक ऐसे ब्राण्ड पर इतनी अधिक धनराशि खर्च नहीं करेगी जिसकी पीक सेल पिछले वर्ष 350 करोड़ रूपयों की रही हो।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट में जो राशि बतायी गई है वह फार्मा कॉरपोरेट द्वारा पिछले कई वर्षों में व्यय की गई कुल मार्केटिंग कोस्ट है। फैडरेशन ऑप मैडिकल सेल्स रिप्रैजेन्टेटिव्ज ऑफ इण्डिया (एफ.एम.आर.ए.आई.) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फार्मा मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डॉक्टर्स पर अपनी दवाईयां लिखने का दबाव बनाने के भ्रष्टाचार को लेकर सावचेत हो गया था। एफ.एम.आर.ए.आई. ने अपनी याचिका में आयकर विभाग पर निगरानी रखने वाले सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस (सी.बी.डी.टी.) की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि डोला-650 के निर्माताओं ने मुफ्त उपहारों के रूप में 1 हजार करोड़ रूपए व्यय किए थे। नियमित फार्मा मार्केट पर यह जनहित याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई थी।

'भद्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आर. पर दिया गया था। सी.बी.आई. ने पहले वॉरंट दिखाया फिर ऑफिस व घर पर तलाशी ली।

हालांकि सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार नहीं दिया गया पर उन्हें आशंका है कि आगामी 2-4 दिन में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

उन्होंने शनिवार को एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा, कि मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति की तारीफ की और कहा कि इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया गया था। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ।

परेशान किए जाने के लिए पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं सी.बी.आई. को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने मेरे परिवार को कोई असुविधा नहीं पहुंचाई। उन्होंने भद्र व्यवहार किया। वे अच्छे अधिकारी थे पर उन्हें ऊपर से आदेश मिला था रेड डालने का।''

पाकिस्तान के प्र.मंत्री ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जताई

- **डॉन अखबार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हवाले से बताया कि, शरीफ ने गुरुवार को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त उच्चायुक्त नील हॉकिन्स के साथ बैठक के दौरान ये विचार व्यक्त किए।**

इस्लामाबाद, 20 अगस्त। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जताई है। उन्होंने समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांतों और कश्मीर मुद्दे के समाधान के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा व्यक्त की है। भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जताने वाले शहबाज शरीफ आंतकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखे हैं। जबकि भारत पाकिस्तान को बार-बार आतंकवाद के खिलाफ एक एक्शन की याद दिलाता रहा है।

पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार से आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच शरीफ ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहायक भूमिका निभाने का भी आग्रह किया। डॉन अखबार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के हवाले से बताया कि शरीफ ने गुरुवार को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त उच्चायुक्त नील हॉकिन्स के साथ बैठक के दौरान ये विचार व्यक्त किए।

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इस संदर्भ में, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद का एक उचित और शांतिपूर्ण समाधान अपरिहार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संबंध में एक सहायक भूमिका निभानी होगी, क्योंकि यह दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। शरीफ की यह टिप्पणी भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर-स्थानीय लोगों को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के निर्णय के कुछ दिनों बाद आई है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले, राज्य संबंधी कानून के तहत केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी मतदान के हकदार थे।

संबंधित घटनाक्रम में, विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए बाहरी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों सहित अस्थायी निवासियों को भी अनुमति देने की भारत की घोषणा को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में तथाकथित चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने और चुनाव पूर्व धांधली और खुले तौर पर हेरफेर के प्रयासों को प्रभावित करने के लिए भारत की सोची समझी रणनीति है।

ई.डी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि अन्य को दस्तावेजों के परीक्षण और इस केस में हुए बैंक लेनदेनों की जांच के बाद तलब किया जाएगा।

इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गढ़ में अपनी पैठ बनाने को लेकर अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे में सिसोदिया को साथ लेकर जा रहे हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात में दिल्ली की भांति ही बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक्स का गठन कर शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी के आप पार्टी के वादे को स्पष्ट करने के लिए सिसोदिया को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। गुजरात में भी बेहतर शिक्षा और इलाज नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

ये दोनों ही सोमवार को गुजरात के हिम्मत नगर और मंगलवार को भावनगर में होंगे। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अपने आवास पर शुक्रवार को मारे गए सी.बी.आई. छापे के बाद सिसोदिया की दिल्ली से बाहर की यह पहली यात्रा होगी।

'भाजपा केजरीवाल में मोदी के खिलाफ सशक्त...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चतुराई पूर्ण प्रबंधन और दिल्ली के स्कूलों तथा एजुकेशन सिस्टम के ''शानदार'' कायापलट को लेकर दिल्ली सरकार को बदनाम करना है।''

सिसोदिया कहते हैं कि आप पार्टी की सरकार पर भाजपा के वर्तमान प्रहार का कारण दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की किसी अन्य द्वारा नहीं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रशंसा करना है। भाजपा आप सरकार को मिली अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा को नहीं पचा पायी और उनके खिलाफ की गई वर्तमान कार्रवाई उनके बॉस केजरीवाल पर भाजपा का एक सीधा प्रहार है।

उन्होंने खुलासा किया कि ''पहले तो उन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को जेल में डाला और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे आशंका है कि उनकी योजना मुझे भी जेल भेजने की है।''

सिसोदिया ने कहा कि देश की जनता ने आप सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की है, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए कार्यों की और इस उपलब्धि ने भाजपा में छटपटाहट पैदा कर दी है।

उन्होंने कहा कि ''आप'' का सुशासन मॉडल और जनता के कल्याण के प्रति केजरीवाल का पूर्ण समर्पण, भाजपा की राजनीतिक नौटंकी और गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें गिराने के तरीके ढूंढने में मोदी के पूर्ण समर्पण के विपरीत है।

सिसोदिया ने कहा कि ''भाजपा शासित केन्द्र सरकार आबकारी घोटाले को लेकर चिंतित है क्योंकि वह उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य चुनौतीपूर्ण के रूप मे देखती है।''

सिसोदिया ने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से इंकार करते हुए कहा कि आबकारी नीति को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि आगामी दिनों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन यह कदम उनकी पार्टी को अच्छे कार्य करने से नहीं रोक पाएगा।

उन्होंने दोहराया कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर गुरूवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर छपी खबर को लेकर केन्द्र सरकार उद्वेलित थी।

सी.बी.आई. ने सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास के अलावा सात राज्यों के 31 अन्य स्थलों पर तलाशी अभियान चलाया। आबकारी नीति के उल्लंघनों को लेकर दर्ज सी.बी.आई. की एफ.आई.आर. में 15 आरोपियों के नामों की लिस्ट है, जिसमें सिसोदिया शीर्ष पर हैं। कुल 11 पृष्ठों के दस्तावेज में जो अपराध सूचीबद्ध हैं, उनमें भ्रष्टाचार, आपराधिक षड़यन्त्र और खातों में हेरा फेरी करना है।

गत नवम्बर माह में लागू की गई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लायसैंस प्राइवेट पार्टियों को दिए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफैंस विंग ने इसकी जांच शुरू की तो सिसोदिया ने इस नीति को वापस ले लिया।

सी.बी.आई. का कहना है कि सिसोदिया ने एक नई नीति लागू की, जिसमें लैफ्टिनैंट गवर्नर की अनुमति के बिना यह तय किया गया कि दिल्ली में शराब बेचने की इजाजत किसे दी जाएगी।

लैफ्टिनैंट गवर्नर दिल्ली में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं।

सी.बी.आई. ने अपनी एफ.आई.आर. में दावा किया कि एक शराब व्यवसायी ने सिसोदिया के साथी की एक कम्पनी को 1 करोड़ रूपए दिए थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्विति में बरती गई अनियमितताओं में शराब कम्पनियां और मध्यस्थ सक्रिय रूप से शामिल थे।

दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सिसोदिया पर छापे पड़ने के बाद गत सायं 12 आई.ए.एस. अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए।

लैफ्टिनैंट गवर्नर ने पिछले माह यह आरोप लगाते हुए सी.बी.आई. जांच की मांग की थी कि आप सरकार ने मनीष सिसोदिया से लेकर सरकार के प्रमुख लोगों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के एक मात्र उद्देश्य को ध्यान में रख आबकारी नीति लागू की थी।

स्टैण्ड अप कमीडियन पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की अनुमति दे दी। और भी खास बात यह रही कि पुलिस ने एहतियातन कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिये तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे।

यह शो शनिवार को हो रहा हैं।

शहर की पुलिस ने भाजपा विधायक टी. राजासिंह को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों का आव्हान किया था कि वे मुनव्वर फारूक़ी के शो में बाधा डालें। भाजपा के इस जनप्रतिनिधि ने कॉमेडियन फारूक़ी के खिलाफ वही कारण दिये थे, जो बेंगलुरू के ऐक्टिविस्टों ने दिये थे। भाजपा विधायक ने कहा था कि फारूक़ी का ट्रैक रिकार्ड हिन्दू देवताओं को अपमानित करने का रहा हैं।

इससे पूर्व, भाजपा विधायक ने कहा था कि अगर शो जारी रहा, तो उनके कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल को आग लगा देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जो कुछ भी घटित होगा, उसके लिये तेलंगाना सरकार एवं पुलिस जिम्मेदार होगी। गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद, भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर कहा कि ''आज मुझे तेलंगाना पुलिस ने नजरबन्द कर दिया है। टी.आर.एस. सरकार पूरी तरह हिन्दू-विरोधी पार्टी हो गई हैं। 22 अगस्त को जो कुछ होगा, उसके लिये टी.आर.एस. सरकार तथा तेलंगाना पुलिस जिम्मेदार होगी।

राजनैतिक विश्लेषक हिन्दुत्व-समर्थक संगठनों की इस कार्यवाही को ऐसी भावनाएं भड़काये जाने के रूप में देख रहे हैं, जो हिन्दू वोटों को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में मदद कर सकती हैं। तेलंगाना में, भाजपा इस मामले में सीधे ही कूद गई है तथा उसने धमकियाँ एवं चेतावनियाँ भी जारी कर दी हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने की टी.आर.एस. के उद्देश्य के साथ भाजपा प्रतियोगिता में आने की कोशिश कर रही हैं। सम्भवत:, किसी मज़ाक को समझ पाने की क्षमता के अभाव में, राजनैतिक दल अपनी आलोचना को लेकर कुछ-कुछ असंवेदनशील हो गये हैं। वस्तुत:, वे कटाक्ष या मज़ाक को समझने में ही असमर्थ हैं।

कॉमेडियनों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान के श्याम रंगीला के साथ हुआ था। रंगीला ने पेट्रोल पम्प को पृष्ठभूमि के रूप में काम में लेते हुये, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कटाक्ष किया, तो उन्हें घेर लिया गया था। पेट्रोल की ऊँची कीमतें एक ऐसा विषय है जिससे सत्तारूढ़ भाजपा के बहुत से लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908